(a) Yes, Sir. Quarter No. 1927, Sector III M. B. Road has been regularised in the name of Smt. Seshamma, after the death of her husband Shri M. Subaiya.

(b) The above quarter has not been converted to hospital pool quarter It continues to be in General Pool.

(c) and (d) When a Government servant, who is an allottee of general pool accommodation retires from service, his/her son, unmarried daughter or wife/husband as the case may be, is allotted accommodation from the general pool on *ad hoc* basis subject to the prescribed conditions. The benefit as mentioned above is permissible only to allottees of general pool accommodation.

It is for the concerned Departments to frame their own rules on various matters regarding allotment/regularisation of accommodation to their employees so far as their Departmental pool accommodation is concerned.

Subletting of Garages of Government Quarters in R. K. Puram

3204. SHRI ASHOK NATH VERMA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some garages of quarters in block Nos. 277 to 284 in Sector 12, R. K. Puram New Delhi have been sub-let by the allottees; and

(b) if so, what action has been taken against the allottees in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) Yes, Sir. A case of sub-letting has been detected in garage attached to quarter No. 283.

(b) Show Cause Notice has been issued to the allottee.

सेवानिवृत्ति के पश्चात् सरकारी आवास

3205. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई मंत्रालय अपने कर्मचारियों को सरकारी आवास तो दे देते हैं लेकिन जब वे सरकारी कर्मचारी सेवा-निवृत्त हो जाते हैं तो वे मंत्रालय इस सुविधा को वापस ले लेते हैं, जिससे उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(ख) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर "हां" हो, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई विशेष रियायत देने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सरकारी आवास आवंटन नियम, 1963 के अनुसार कोई सरकारी कर्मचारी उन्हें आवंटित सामान्य पूल आवास को अपनी सेवा-निवृत्ति के पश्चात् चार माह की अवधि के लिए साधारण लाइसेंस फीस का भुगतान करने पर अपने पास रखने का पात्र है। इसके अतिरिक्त, विशेष परिस्थितियों में सरकार अधिकतम चार माह तक आगे और आवास रखने की अनुमति प्रदान करती है। सामान्य पूल आवास की अत्यधिक कमी को ध्यान में रखते हुए इस सम्बन्ध में बढ़ी हुई लाइसेंस फीस के भुगतान पर सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारियों को आगे और रियायत अनुज्ञेय नहीं है।

Provision of Sewerage and Telephone Lines for New Housing Colonies in Pitampura

3206. SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of housing colonies, sponsored by

various Group Housing Societies, are fast nearing completion at Pitampura on the Outer Ring Road, opposite Mangolpuri;

(b) if so, whether the sewerage line for these colonies has been laid;

(c) whether electric, water and telephone lines for these colonies are available, and

(d) if the answer to parts (b) and (c) above be in the negative, what steps Government propose to take to expedite provision of these service?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (d) The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

दिल्ली नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जा

@3207. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम की जमीन पर अभी भी अवैध कब्जों का सिलसिला जारी है ;

(ख) यदि हां, तो अभी तक इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है और ऐसे मामलों की वर्षवार संख्या क्या है जो विगत पांच वर्षों के दौरान दिल्ली नगर निगम द्वारा न्यायालयों में दायर किए गए थे और जिनका फैसला निगम के पक्ष में गया और

(ग) गत वर्ष निचली अदालत व उच्च अदालत द्वारा जमीन के विवादों के संबंध में कितने मामलों में नगर निगम के विरुद्ध न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया ?

@पूर्वत: अतारांकित प्रश्न 2816, 22 मार्च, 1988 से स्थानान्तरित ।

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) : कुछ पुराने अतिक्रमण अभी विद्यमान है । अधिकांश मामलों में अतिक्रमणों को पुलिस की सहायता से और उसके बिना हटा दिया गया है । यद्यपि, दिल्ली नगर निगम ने अतिक्रमणों के विरुद्ध कोई मामला दर्ज नहीं किया है, फिर भी दिल्ली नगर निगम के हटाने की कार्यवाही के विरुद्ध अतिक्रमणकारियों ने न्यायालय से रोकादेश प्राप्त कर लिया था तथा ऐसे सभी मामले अभी भी न्यायाधीन हैं ।

Allotment of DDA Flats to Freedom Fighter in Delhi

@@3208. SHRI SHANTI TYAGI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what is the number of freedom fighters in the Union Territory of Delhi at present;

(b) whether Government have earmarked any quota for freedom fighters for the allotment of DDA flats in the city; and

(c) if so, what are the details thereof and if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) 1870 freedom fighters are getting Central pension. Besides this 626 widows of freedom fighters also are getting pension from Central Government.

(b) No, Sir.

(c) In view of the reply to part (b) question of giving details does not arise. On the recommendations of the Committee of Experts on the Working of DDA (Baveja Committee) all reservations except under mentioned were abolished in January, 1979:—

(i) Widows of defence personnel killed in action	1%
(ii) Ex-servicemen	1%
(iii) Physically handicapped persons	1%
(iv) Scheduled Castes and Scheduled Tribes	25%

@@Previously Unstarred Question 2821 transferred from 22nd March, 1988.